>

Title: Need to protect the interest of ASHA midwives in the country.

डॉ. संजय सिंह (सुल्तानपुर): सभापति महोदय, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रात हो या दिन, जननी केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत आशा बहुं कार्यरत हैं। उत्तर प्रदेश में आशा बहुओं की योजना भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत वर्ष 2005 से संचालित है। उत्तर प्रदेश में आशा बहुओं की संख्या लगभग 4 लाख है। जैसा आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में हजारों, करोड़ो रुपये का घोटाला हुआ है। कहीं अस्पताल है तो डाक्टर नहीं हैं, डाक्टर हैं तो वे प्रैक्टिस नहीं करते। गांव में कहीं भी एएनएम सैंटर नहीं हैं, एएनएम सैंटर है तो एएनएम नहीं है।

मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो आशा बहुं हर समय हर गांव में, रात में, जाड़े में, गर्मी में, बरसात में जहां शिशु पैदा होता है, उसकी हर सहायता में लगी रहती हैं, उन्हें केवल 600 रुपये मानदेय मिलता है। वे न राज्य कर्मचारी हैं और न ही उनका कोई सम्मान है। आज हर जिले में सीएमओज़ उनका आर्थिक शोषण करते हैं।

मैं आपके माध्यम से सदन और सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उन्हें कम से 10 हजार रुपये मासिक वेतन मिले, राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए और एएनएम भर्ती प्रक्रिया में प्रथम वरीयता दी जाए। उनका जो आर्थिक शोषण हो रहा है, उसे रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया जाए।